(b) if so, the estimated expenditure involved therein and the likely increase in ship repair capacity as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) Yes Sir.

(b) The estimated expenditure involved therein is Rs. 71.34 crores and the likely capacity for ship repair after modernisation will be 106 vessels per year.

Involvement of Private Sector and Foreign Collaboration in Ship Building

2579. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to involve private sector and foreign collaborators in the ship building industry; and

(b) if so, what is the response from the foreign companies thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) According to the new Industrial Policy announced by the Government in July, 1991, Shipbuilding Industry has been delicensed except for construction of war ships which has been reserved for the public sector. Further, mechanised sailing vessels upto 10.000 DWT have been allowed automatic approval for foreign technology and foreign equity participation upto 51% as per the laid down procedure. Entrepreneurs in the private sector can set up new shipyards in the country with foreign collaboration as necessary.

(b) Some of the foreign companies have shown interest in technical collaboration with the Indian Shipyards.

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा उन्हें जोड़ा जाना

2580. श्री महेश्वर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चण्डीगढ़-मनाली को मण्डी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से वाया बाजौरा-कांडी सम्पर्क सड़क के द्वारा तथा चण्डीगढ़-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को शिमला-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाया जलोड़ी सम्पर्क सड़क के द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां । राज्य सरकारों ने नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए 135 सड़कों के प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कें शामिल हैं और राज्य वार प्रस्तावों का सारांश विवरण रूप में संलग्न है [नीचे देखिए ।]

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित किए जाने हेतु, बाजोरा-कांडी के माध्यम से एन० एच० 20 और एन० एच० 21 को जोड़ने के लिए, एक प्रस्ताव भेजा है । तथापि, संसद द्वारा मई, 1988 में पारित संशोधित सकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तावक वृद्धि न होने के कारण इस प्रस्ताव को मंजूरी देना संभव नहीं हुआ है । एन० एच० 21 और 22 को वाया जालोरी जोड़ने के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का सारांश।

क्र० सं०	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	अनुमानित लम्बाई कि०मी०
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	19	6045
2.	असम	3	380
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	400
4.	बिहार	5	1180
5.	गुजरात	9	2271
6.	हरियाणा	4	586
7.	हिमाचल प्रदेश	2	618
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	400
9.	केरल	5	300
10.	कर्नाटक	13	4425
11.	महाराष्ट्र	11	4679
12.	मणिपुर	1	190
13.	मेघालय	2	220
14.	मध्य प्रदेश	14	6656
15.	मिजोरम	2	205
16.	नागालैंड	1	220
17.	उड़ीसा	2	700
18.	पांडिचेरी	1	39
19.	पंजाब	5	915
20.	राजस्थान	5	1480
21.	सिक्किम	1	30
22.	तमिलनाडू	16	3355
23.	त्रिपुरा	1	135
24.	उत्तर प्रदेश	6	1642
25.	पश्चिम बंगाल	5	495
	कुल :	135	37,566 कि०मी०